कानपुर, शुक्रवार, 09 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 13, पृष्ठः 8+4
प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी
सच्चाई के दम पर जोश के साथ...
www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड गन्ना किसानों की जेब पर डाका नहीं ...>Pg12
गैंगरेप का आरोपी कथित पत्रकार गिड़गिड़ाया... > Pg03

मूल्यः 2 ₹

जमीन के बदले नौकरी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किये आरोप

लालू का 'कुनबा' जाएगा जेल!

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा आदेश देते हुए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, पुत्री मीसा भारती समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपितों के खिलाफ सुनवाई योग्य मामला बनता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मामला केवल कुछ अलग-अलग सौदों तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि एक संगठित आपराधिक गतिविधि की ओर इशारा करता है। आदेश में यह भी कहा गया कि सभी आरोपितों की भूमिकाएं आपस में जुड़ी प्रतीत होती हैं और उन्होंने साझा उद्देश्य के तहत काम किया।

सीबीआई के अनुसार, रेलवे में नियुक्तियों के बदले अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से जमीन ली गई, जिसे कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम ट्रांसफर कराया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि नौकरी, जमीन और संपत्ति के लेनदेन को एक सुनियोजित ढांचे के तहत अंजाम दिया गया। यह तरीका किसी एक-दो नियुक्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे एक पैटर्न के रूप में अपनाया गया।

अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें पर्याप्त सबूत न होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर यह केवल देखा जाता है कि अभियोजन के पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं, और इस कसौटी पर अभियोजन सफल रहा है। अब मामले में नियमित ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें गवाहों की पेशी और साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जाएगी। अदालत के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे कानून के राज की जीत बताया है, जबकि आरजेडी की ओर से इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देने के संकेत मिलते रहे हैं। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया है कि आगे की पूरी कार्यवाही कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।

- सीबीआई अदालत ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित 41 आरोपितों पर तय किए आरोप
- कोर्ट ने कहा, यह अलग-अलग सौदे नहीं, संगठित आपराधिक गतिविधि का मामला

क्या है 'जमीन के बदले नौकरी' मामला?

सीबीआई के मुताबिक यह मामला उस दौर से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के ग्रुप-डी समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के बदले अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से जमीन ली गई। ये जमीनें बेहद कम कीमत पर या बिना समुचित भुगतान के लालू परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम दर्ज कराई गईं। जांच एजेंसी का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया सुनियोजित और संगठित तरीके से अंजाम दी गई।

ईडी कार्रवाई के विरोध में टीएमसी का कोलकाता से दिल्ली तक कोहराम

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। प्रदर्शन शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सांसदों को वहां से हटाया और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, कीर्ति आज़ाद समेत कई नेता शामिल थे। इस दौरान गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। हिरासत में लिए जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश देख रहा है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाइयों से चुनाव नहीं जीत पाएगी।

- पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ लगाए नारे

वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आज़ाद ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पूरी तरह गलत और अलोकतांत्रिक है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार चुनाव जीतने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। इसी तरह शताब्दी रॉय ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याद आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एजेंसियों को आगे किया जा रहा है, लेकिन इससे चुनावी नतीजे नहीं बदले जा सकते।

दरअसल, यह विवाद उस वक्त और गहरा गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित कोयला तस्करी मामले में राजनीतिक परामर्श देने वाली संस्था 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आई-पैक) के कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान पार्टी से जुड़े अहम दस्तावेज, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, उम्मीदवारों की सूची और रणनीतिक जानकारियां जब्त की गईं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमित शाह पश्चिम बंगाल जीतना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें।

हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एजेंसी का कहना है कि यह छापेमारी ठोस सबूतों के आधार पर की गई है और इसका किसी राजनीतिक दल या चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। एजेंसी के अनुसार यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं।

10वीं की छात्रा से रेप, कोचिंग संचालक पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार

» कोचिंग जाने से मना करने पर परिजनों को बताई शिक्षक की करतूत

» पुलिस ने शुरू की जांच, छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा

»प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर।किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कोचिंग संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़ित छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है।

परिजनों के अनुसार पीड़िता कक्षा 10 की छात्रा है और किदवई नगर क्षेत्र स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। आरोपी उसी स्कूल में अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ है और साथ ही इलाके में एक निजी कोचिंग संस्थान का संचालन करता है, जहां छात्रा पढ़ने जाती थी। आरोप है कि आरोपी ने डर और दबाव का माहौल बनाकर छात्रा के साथ अनुचित कृत्य किया। गुरुवार सुबह जब छात्रा ने कोचिंग जाने से इनकार किया तो परिजनों ने कारण पूछा। इस पर छात्रा ने रोते हुए पूरी आपबीती बताई। जानकारी मिलते ही परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई।पुलिस का कहना है कि पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जा रही है। वैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चिकित्सीय परीक्षण और बयान दर्ज किए जा रहे हैं।आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच संवेदनशीलता से की जा रही है।

वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन-2026 का

कानपुर में सैन्य अनुशासन से स्वागत

शौर्य के कदम, क्रांति की ओर के संदेश के साथ आगे बढ़ रही साइक्लोथॉन

»प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर।वीर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉनड्ढ2026 के तहत रांची से नई दिल्ली जा रही एनसीसी साइक्लोथॉन टीम का एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर, कानपुर में भव्य स्वागत किया गया।इस अवसर पर सैन्य अनुशासन, देशभक्ति के उत्साह के साथ महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वीर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।एनसीसी मुख्यालय परिसर में उपस्थित एनसीसी अधिकारी, कैडेट्स ने टीम का सैन्य प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया। इस दौरान कैडेट्स ने लोक नृत्य तथा वीर बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया । फ्रशौर्य के कदम, क्रांति की ओरफ्र के संदेश के साथ आगे बढ़ रही यह साइक्लोथॉन युवाओं में शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित कर रही है। यह पहल एनसीसी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।साइक्लोथॉन टीम का नेतृत्व कर्नल अनिल कुमार व लेफ्टिनेंट कर्नल पी.बी. शर्मा कर रहे हैं। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर पी.के. शास्त्री, ग्रुप कमांडर, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर कानपुर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में वीर बिरसा मुंडा के साहस, बलिदान, सामाजिक न्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष के आदर्शों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। वहीं टीम लीडर कर्नल अनिल कुमार ने कहा कि यह साइक्लोथॉन युवाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाते हुए अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है।कानपुर में रात्रि विश्राम के उपरांत साइक्लोथॉन टीम ने शनिवार को आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। साइक्लोथॉन का समापन नई दिल्ली में होगा।जहाँ 27ड्ढ28 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस कैंप (आरडीसी) के दौरान टीम भाग लेगी। साइक्लोथॉन टीम को सम्मानित भी किया जाएगा।

नाबालिग से गैंग रेप का मामला गर्माया

गैंगरेप का आरोपी कथित पत्रकार गिड़गिड़ाया

बोला- मुझे फंसाया गया, लड़की को कभी देखा नहीं, स्कॉर्पियो में दरोगा के साथ नहीं की दरिंदगी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। साहब, मैंने रेप नहीं किया। उस लड़की को न कभी देखा, न कभी बात हुई। आप मेडिकल करा लीजिए। मैं निर्दोष हूं। अगर दोषी मिलता हूं, तो जेल भेज दीजिएगा। मुझे रंजिशन फंसाया जा रहा है।

सोमवार रात अमित दरोगा का फोन आया। कहा, आरपीएफ में नए इंस्पेक्टर आए हैं। लोहा चोरी हुआ है, मिलना चाहते हैं। अपने पत्रकार साथियों से पता करो। हम बाइक से 35 नंबर सोना क्रॉसिंग पहुंचे। वहां आरपीएफ इंस्पेक्टर मिले, साथ में अमित दरोगा थे। इसी बीच लड़के अपनी बहन को ढूंढते हुए आए। मुझे भी देख लिया, तो मेरा भी नाम लिख दिया। क्रॉसिंग के पास फिंगर का ठेला लगाने वाले लड़के से लड़की का अफेयर चल रहा है। उससे पता करा लीजिए। वह उससे मिलता रहता है। जांच करा लीजिए, पूरी सच्चाई सामने निकलकर आ जाएगी। ये बातें रो-रोकर गैंगरेप के आरोपी पत्रकार शिवबरन सिंह यादव ने पुलिस के सामने बताईं। कानपुर के सचेंडी थाने में मंगलवार को 14 साल की लड़की ने बिठूर में तैनात दरोगा अमित मौर्या और पत्रकार शिवबरन पर गैंगरेप की फिर दर्ज कराई है। पत्रकार शिवबरन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दरोगा अभी फरार है। उसकी तलाश में चार टीमें लगी हुई हैं। मामले में लापरवाही बरतने पर डीसीपी वेस्ट को हटा दिया है।

स्कॉर्पियो से लड़की को किडनैप किया!

सचेंडी थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की ने बताया- मैं सोमवार रात करीब 10 बजे घर से निकली थी। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार दो लड़कों ने मुझे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। इनमें एक पुलिस वाला था। आरोपी सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले गए। दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर ही मेरे साथ गैंगरेप किया।

आरोपी दरोगा की धमकियों से परिजन डरे

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद से उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। मेडिकल के बाद भी पुलिस ने उसे घर नहीं भेजा। परिजनों के अनुरोध पर पुलिस ने कहा कि कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद ही घर भेजा जाएगा। उसे रात करीब 3 बजे छोड़ा गया। आरोपी दरोगा की लगातार धमकियों से परिजन डरे हुए हैं।

हाल ही में दरोगा का हुआ था तबादला

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कुछ समय पहले तक आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्या भीमसेन चौकी प्रभारी था। कुछ दिन पहले डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने उसका तबादला बिठूर थाने में किया था, लेकिन अभी उसकी रवानगी नहीं हुई थी। भीमसेन चौकी के नए प्रभारी छुट्टी पर थे। इसी दौरान दरोगा का क्षेत्र में आना-जाना बना रहा। जांच में सामने आया है कि दरोगा की पत्रकार शिवबरन से दोस्ती है और दोनों को साथ जाते हुए देखा गया था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने स्पष्ट किया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कहां चला जाए।

घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो जब्त

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में बिठूर में तैनात दरोगा अमित मौर्या और पत्रकार शिवबरन का नाम लिया। इसके बाद दोनों को मुकदमे में नामजद किया गया। घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो (अप 78 जेजे 9331) को पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह स्कॉर्पियो दरोगा अमित कुमार मौर्या की है। घटना के समय दरोगा की सचेंडी में मौजूदगी पाई गई है, जबकि उसकी तैनाती बिठूर थाने में थी। फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए- मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह को सौंपी गई है। एडीसीपी वेस्ट ने बुधवार को जांच शुरू की। वह सबसे पहले सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे पहुंचे, जहां पीड़िता ने अपने साथ गैंगरेप होने की बात बताई थी। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल के आसपास मौजूद दुकानदारों से पूछताछ की। वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत भी जुटाए।

पत्रकार ने सफाई में क्या-क्या कहा ?

पत्रकार ने बताया कि सोमवार रात आरपीएफ इंस्पेक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा- भीमसेन के पास रेलवे लाइन से लोहा काटा गया है, चोरी का खुलासा कराओ, ऊपर से आदेश हैं। इस पर मैंने उनसे कहा- सर, जानकारी करेंगे। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं बाइक से पहुंचा। वहां दरोगा अमित मिले। आधे घंटे तक हम अमित दरोगा की स्कॉर्पियो में बैठे रहे। इंस्पेक्टर सफेद कार से आए। काफी देर तक हम लोगों में बातचीत हुई। इसके बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर चले गए। मैं भी बाइक से घर लौट रहा था, तभी याद आया कि मफलर दरोगा की स्कॉर्पियो में ही छूट गया। मैंने दरोगा को फोन किया, तब उन्होंने कहा कि मैं अभी यहीं हूं। मैं दरोगा के पास पहुंचा तो शंकरपुरवा के दो लड़के आ गए। हमने उनसे पूछा- यहां क्या कर रहे हो? लड़कों ने कहा- हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद मैं घर चला आया। अगले दिन यानी मंगलवार सुबह मैं फिर बाइक से जा रहा था। उस वक्त खेत में कुछ लोग पानी लगा रहे थे। जो लड़के सोमवार को मिले थे, वे चिल्लाकर कह रहे थे- एक दरोगा आए थे और एक गोरा लड़का था, उसी ने मेरी बहन से छेड़छाड़ की। मैं तुरंत दौड़कर उनके पास गया। पूछा- तुमने हमें छेड़छाड़ करते देखा था क्या, झूठ मुझे क्यों फंसा रहे हो? जवाब मिला- नहीं, बहन ने ये सब बताया है। हमने कहा कि बहन को बुलाओ, तो वह लड़का बोला कि मेरी बहन चौकी गई है, जिसके बाद मैं तुरंत चौकी भागकर आया। मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा हूं कि मुझे क्यों फंसाया गया है।

गैंगरेप केस में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट भी नाराज

5 जनवरी की रात को गैंगरेप होने के बाद 8 जनवरी को पीड़िता को कोर्ट लाया गया। यहां पहले तो 3 घंटे तक पुलिस जांच अधिकारी नहीं पहुंचे। पीड़िता रूम के बाहर बैठी रही। जब जांच अधिकारी पेश हुए, तो जज ने पूछा- लड़की 14 साल की है, मगर आपने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज ही नहीं किया है। पहले जाइए, पॉक्सो में स्वतःदर्ज करिए, तब पीड़िता के बयान दर्ज कराने आइएगा। कोर्ट की नाराजगी के बाद पीड़िता के बयान दर्ज नहीं हो सके। पुलिस पीड़िता को नोएडा नंबर की लाल रंग की कार में बैठाकर चली गई। पुलिस ने क्यों पॉक्सो एक्ट में मुकदमा नहीं लिखा, इसका जवाब पीड़िता के भाई ने दिया। उन्होंने कहा- आरोपी खुद विभाग में दरोगा है, इसलिए जानबूझकर केस हल्का किया गया। हमें 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, मगर बयान तक नहीं हो पा रहे हैं। हम पर दबाव बनाया जा रहा है, लोग घर की रैकी कर रहे हैं।

क्यूआर कोड स्कैन करते ही पता चला जाएगा कहां है रैन बसेरा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जिला प्रशासन हाईटेक होता जा रहा है। अब रैन बसेरा कहां कहां हैं और आपके नजदीक कौन सा है यह सब क्यूआर कोड से पता कर सकेंगे। शहर में एक नई तकनीकी पहल शुरू की गई है। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर त्वरक कोड युक्त स्टिकर लगाए गए हैं। इन्हें स्कैन करने पर संबंधित क्षेत्र के रैन बसेरों की लोकेशन, उपलब्ध सुविधाएं और केयरटेकर का मोबाइल नंबर एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगा। इससे यात्रियों, प्रवासियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को रैन बसेरों की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।

➪ जिला प्रशासन ने सहूलियत के लिए जारी किया क्यूआर कोड, एसडीएम सदर ने बांटे कंबल देखीं व्यवस्थाएं

ठंड के बीच जिला प्रशासन ने राहत अभियान तेज कर दिया। तहसील सदर क्षेत्र में देर रात्रि तक विशेष अभियान चलाकर सड़क किनारे खुले में जीवन गुजार रहे जरूरतमंदों को ठंड से बचाने की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक टीमें शहर के उन इलाकों में पहुंचीं, जहां ठंड का असर सबसे अधिक देखा जा रहा था एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने बताया कि शीत-लहर के दौरान खुले में रह रहे लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों की क्षमता, साफ-सफाई, कंबल और हीटर की व्यवस्था पर लगातार निगरानी की जा रही है और ठंड की अवधि में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उपजिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह और तहसीलदार सदर विनय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने प्रमुख चौराहों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास डेरा डाले लोगों से सीधा संवाद किया। मौके पर कंबल वितरित किए गए और खुले में सो रहे लोगों को निकटस्थ रैन बसेरों में पहुंचाकर सुरक्षित आश्रय दिलाया गया। कई स्थानों पर टीम ने लोगों को समझाकर खुले में रुकने से रोका।

जुमा की नमाज से पहले सेंट्रल जोन में पुलिस का रूट मार्च

» डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में कर्नलगंज से चमनगंज तक पैदल गश्त

» व्यापारियों और नागरिकों से संवाद, शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। जुमा की नमाज के मद्देनज़र शांति एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए शुक्रवार को सेंट्रल जोन में पुलिस ने व्यापक पैदल गश्त और रूट मार्च किया। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस बल और पीएसी के साथ सद्भावना चौकी चौराहे से रूट मार्च की शुरुआत की गई।

रूट मार्च के दौरान थाना क्षेत्र कर्नलगंज, अनवरगंज, बेकनगंज और चमनगंज के मुख्य बाजारों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारियों

और पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से संवाद कर शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। रूट मार्च के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त अनवरगंज, संबंधित थाना प्रभारी, पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी के जवान मौजूद रहे।

माघ मेला को लेकर आरपीएफ अलर्ट, आईजी ने की समीक्षा बैठक

सेंट्रल स्टेशन पर 17 तथाकथित 'चोर रास्तों' को तत्काल बंद करने के निर्देश

» संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर मध्य रेलवे के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) आरपीएफ प्रदीप गुप्ता ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का दौरा किया। माघ मेला के मद्देनज़र उन्होंने स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आरपीएफ एवं संबंधित अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।

बैठक के दौरान आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने स्टेशन पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निगरानी बढ़ाने, प्लेटफॉर्म व सर्कुलेटिंग एरिया में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।आईजी ने खानपान सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष नजर रखने को कहा, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद 17 तथाकथित 'चोर रास्तों' को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीनियर डीएससी से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी, ताकि असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लग सके।आईजी प्रदीप गुप्ता ने अधिकारियों को माघ मेला अवधि के दौरान निरंतर गश्त, प्रभावी चेकिंग और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

शोक संदेश

ॐ शांति ॐ शांति

मान्यवर,
अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिता

श्रद्धेय विष्णु त्रिपाठी जी
(वरिष्ठ पत्रकार)

का स्वर्गवास दिनांक 29 दिसम्बर 2025 दिन सोमवार को हो गया था।
अतः दिवंगत आत्मा की शांति हेतु।

!! तेरहवीं कार्यक्रम व शांति हवन !!

दिनांक 10 जनवरी 2026, दिन– शनिवार को दोपहर 2:00 बजे से होना सुनिश्चित हुआ है। अतः आप प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें।
आपकी उपस्थिति हमें संबल प्रदान करेगी।

कार्य स्थल
निवास– 51, पत्रकारपुरम, कानपुर नगर।

अमित त्रिपाठी, शांतनु त्रिपाठी
एवं समस्त त्रिपाठी परिवार
मो. 9415130578, 9554999969

सम्पादकीय

मौतें सबसे स्वच्छ शहर पर कलंक

यह शर्मनाक है कि जिस शहर को पिछले सात सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दिया जा रहा था, वहां पेयजल में सीवर का पानी मिल जाने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाए। बताया जाता है कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर के पानी के रिसाव से हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। घटनाक्रम के बाद सौ के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हुए और सैकड़ों लोग दूषित पेयजल के उपयोग से बीमार हैं। वैसे भी किसी सभ्य समाज में व्यक्ति आत्मग्लानि से यह सुनकर बीमार हो जाएगा कि जिस पानी को उसने उपयोग किया, उसमें सीवर का गंदा पानी मिला था। निस्संदेह, यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही ही है, जिसके चलते हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। नगर निगम ही नहीं, इस महकमे से जुड़े सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल, इंदौर लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल करता रहा है तो इस दुर्घटना ने पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बना दिया। इस दुखद स्थिति के चलते मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिये बाध्य होना पड़ा। विडंबना यह है कि नागरिकों ने पहले ही दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत की थी, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जवाबदेह अधिकारी तब हरकत में आए, जब कई लोगों की जान जा चुकी थी। यहां तक कि इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का महकमा आता है, उनकी संवेदनहीन बयानबाजी ने लोगों का आक्रोश बढ़ाया है। हालांकि, तल्ख आलोचना के बाद मंत्री ने खेद जताया है। यहां तक कि इस घटना के बाद मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने भी दोषियों से प्रायश्चित करने व दंड देने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ छोटे स्तर के अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण से इन मौतों के लिये जिम्मेदार लोगों का प्रायश्चित हो पाएगा?लेकिन विडंबना है कि यह समस्या केवल इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के छोटे-बड़े शहरों में गाहे-बगाहे दूषित जल आपूर्ति के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। दुर्घटना के बाद जांच समितियों का गठन, मुआवजे की घोषणा और कनिष्ठ अधिकारियों का निलंबन मामले में लीपापोती का उपक्रम बन चुका है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण' के मंत्र पर जोर दिया था। तब उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जीवनयापन को सुगम बनाने के लिये प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया था।आवश्यकताओं से वंचित रखा जाएगा तो जीवनयापन को सुगम कैसे बनाया जा सकता है? मध्य प्रदेश की दोहरे इंजन वाली सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। इंदौर की त्रासदी दर्शाती है कि शहरी बुनियादी ढांचे के खराब रखरखाव के कारण इस अधिकार का उल्लंघन कितनी आसानी से हो सकता है। निष्कर्ष यह भी है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और शासन संबंधी नारे व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। इंदौर की घटना के बाद देश के सभी राज्यों में संबंधित विभागों व स्थानीय निकायों को पेयजल से जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा।

आस्था कोई भी हो मगर इंसान अच्छा हो

यशवंत सचदेव

यदि हिंदू हूं तो अच्छा हिंदू बनूं, मुसलमान हूं तो बेहतर मुसलमान बनूं, ईसाई हूं तो अच्छा ईसाई बनूं। और यह अच्छा होने का मतलब है अच्छा इंसान होना। अच्छा इंसान यानी वह जो अपनी आस्था में पूरा विश्वास रखने...यदि हिंदू हूं तो अच्छा हिंदू बनूं, मुसलमान हूं तो बेहतर मुसलमान बनूं, ईसाई हूं तो अच्छा ईसाई बनूं। और यह अच्छा होने का मतलब है अच्छा इंसान होना। अच्छा इंसान यानी वह जो अपनी आस्था में पूरा विश्वास रखने के बावजूद दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें। लगभग दो दशक पुरानी बात होगी। हमारे समय के एक महत्वपूर्ण संगीतकार खैयाम साहब के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के बाद लौट रहे थे हम। उस कार्यक्रम में जो वे नहीं कह पाये थे, वही सब बता रहे थे वे। मेरी भूमिका तो सिर्फ श्रोता की थी। अचानक वह बोलते-बोलते रुक गये। कार की खिड़की से दायीं ओर देख रहे थे वे। उनके दोनों हाथ जुड़ गये थे। सिर झुक गया था उनका। मैंने देखा हमारी कार मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से गुजर रही थी। 'आपके धर्म में तो मूर्तिपूजा मना है,' मैंने अनायास ही जैसे उनसे पूछ लिया। वे मुस्कुराये, 'आदत है,' उन्होंने कहा। और फिर इसके बाद हम हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर बात करने लग गये थे।

आज जब मैं यह लिख रहा हूं, अचानक मुझे खैयाम की यह बात याद आ गयी। इसके साथ ही एक और बात भी याद आ रही है। मेरी बेटी कान्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है। स्कूल छोड़े उसे दशकों बीत गये। पर अब भी जब वह अपने बचपन के स्कूल के सामने से गुजरती है तो अनायास उसके हाथ 'क्रॉस' बनाने की मुद्रा में हरकत करने लगते हैं। और अपनी बात करूं? मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हुए मेरा सर भी, जैसे अपने आप झुक जाता है। और मैं यह भी जानता हूं कि पूजा?हों के प्रति यह रवैया सिर्फ खैयाम, मेरी बेटी, या मेरा ही नहीं है? हम जैसे न जाने कितने हैं जो ऐसा करते हैं। और यह सब अनायास हो जाता है। लेकिन कैसे?इस सवाल का जवाब तो यही है कि ऐसा करने के लिए किसी ने हमें कहा नहीं। मैंने अपनी बेटी से यह कभी नहीं कहा कि वह ऐसा किया करे। आप चाहें तो इसे संस्कारों का परिणाम कह सकते हैं। यह तो संभव है कि मैंने बेटी से कभी यह कहा हो कि सब धर्म समान होते हैं, पर मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी उसे समान मानने के लिए भी कहा हो। कम से कम मेरी तरफ से ऐसा कोई दबाव बच्चों पर नहीं डाला गया। मेरे माता-पिता ने भी कभी ऐसा कोई दबाव हम भाई-बहनों पर नहीं डाला। उस दिन सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से गुजरते हुए खैयाम साहब का अनजाने में ही सिर झुकाना भी किसी दबाव का परिणाम नहीं था। उन्होंने बताया था कि वे न जाने कब से ऐसा करते आ रहे हैं, और यह भी बताया था उन्होंने कि 'पूजाग?ह के सामने सिर झुकाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर धरा गया है।' सच है, आशीर्वाद का यह अहसास मंदिर, मस्जिद, चर्च, या गुरुद्वारा, सब देते हैं। और सब धर्मों का आदर करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सर्व धर्म समभाव की संस्कृति है हमारी। हमारा धर्म, यानी हिंदू धर्म, हमें यह सिखाता है कि चाहे ईश्वर कहें या खुदा, गॉड कहें या एक ओंकार, अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, पर पहुंचते सभी एक ही जगह हैं? हम यह अलग-अलग रास्ते! जैन धर्म का एक सिद्धांत है? अनेकांत वाद। यह विचार हमें समझाता है कि मैं सही हूं, पर तुम भी सही हो सकते हो। इतनी-सी बात यदि हम समझ लेते हैं तो फिर कोई विवाद बचता ही नहीं है। बस इतनी-सी बात समझने की आवश्यकता है कि हमारा अलग-अलग धर्म का होना एक संयोग मात्र है। मैं किसी एक धर्म में विश्वास करने वाले परिवार में पैदा हुआ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरे माता-पिता हिंदू थे, इसलिए मैं भी हिंदू हो गया, वे मुसलमान होते तो मैं आरती की जगह नमाज़ पढ़ रहा होता। इस संदर्भ में मेरी कोई भूमिका हो सकती है ।

नयी शिक्षा नीति के समक्ष मौजूद कानूनी बाधाएं

एनईपी का क्रियान्वयन

डा0 सुधीर कुमार

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवा पीढ़ी की तकदीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने एनईपी के प्रावधानों को सबसे पहले अपनाया व शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए। यह प्रमाण है कि अकादमिक स्वतंत्रता से सरकारी संस्थान भी नवाचार के केंद्र बन सकते हैं। बशर्ते कानूनी बाधाओं को दूर किया जाये।भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह 21वीं सदी के बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की नई आकांक्षाओं का जीवंत प्रतिबिंब है। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई यह नीति शिक्षा जगत में उस 'पैराडाइम शिफ्ट' की वकालत करती है, जिसका इंतज़ार भारत का युवा और बौद्धिक वर्ग दशकों से कर रहा था। यह नीति जहां एक ओर लचीलेपन, कौशल विकास और बहुविषयक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत को 'विश्व गुरु' बनाने का स्वप्न देखती है, वहीं इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की राह में कई सूक्ष्म प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं भी मौजूद हैं।

इस नीति की वास्तविक सफलता और विफलता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसका 'कानूनी कार्यान्वयन' है।

इस वैचारिक यात्रा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने प्रेरणादायक पहल की है।जब देश के कई राज्य और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इस नीति के जटिल नियमों और बदलावों को समझने की जद्दोजहद में उलझे थे, तब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने दूरदर्शिता का परिचय दिया।

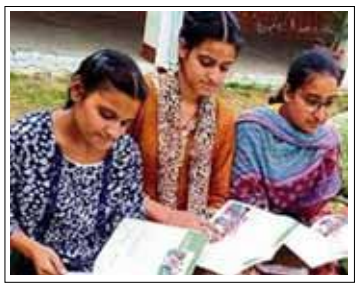

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश के उन अग्रणी संस्थानों में शामिल हुआ, जिसने एनईपी के प्रावधानों को सबसे पहले अपनाया व अपने शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किए। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को एनईपी के सफल क्रियान्वयन के लिए 'प्लेटिनम अवार्ड' से नवाजा गया।शिक्षा जगत में प्रायः एनईपी के शैक्षणिक लाभों जैसे रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति और कौशल आधारित शिक्षा - पर व्यापक चर्चा होती है, लेकिन इसके 'कानूनी पेचों' पर खामोशी बरती जाती है। इन 'साइलेंट' समस्याओं को सुलझाए बिना नीति का पूर्ण लाभ मिलना दुष्कर है। सबसे बड़ी चुनौती 'संवैधानिक विरोधाभास' की है। संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जब केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति लागू करती है, तो राज्यों के अपने विश्वविद्यालय अधिनियमों के साथ उसका स्वाभाविक टकराव होता है। मसलन, एनईपी 'मल्टीपल एंट्री और एग्जिट' की सुविधा देती है। कानूनन, यदि एक छात्र एक राज्य के विश्वविद्यालय से एक वर्ष बाद सर्टिफिकेट लेकर निकलता है और दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय में डिप्लोमा में प्रवेश चाहता है, तो दोनों राज्यों के नियमों में भिन्नता छात्र का भविष्य संकट में डाल सकती है। इस 'क्रेडिट ट्रांसफर' की कोई ठोस कानूनी गारंटी स्पष्ट नहीं है।दूसरा महत्वपूर्ण और मौन मुद्दा 'स्वायत्तता बनाम नियंत्रण' का है। नीति कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने का प्रस्ताव करती है, लेकिन प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के तहत चार अलग-अलग वर्टिकल - नियमन, मान्यता, वित्त पोषण और मानक निर्धारण - कैसे एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना काम करेंगे, यह एक कानूनी भूलभुलैया बनी हुई है। यहां शक्ति के केंद्रीकरण का अंदेशा भी रहता है, जो लंबी कानूनी लड़ाइयों और मुकदमों का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल संप्रभुता और डेटा सुरक्षा एक गंभीर पहलू है जिस पर पर्याप्त बहस की आवश्यकता है।

लॉकर के माध्यम से करोड़ों छात्रों का संवेदनशील शैक्षणिक इतिहास ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ऐसे में डेटा हैक होने या दुरुपयोग होने की स्थिति में कानूनी जवाबदेही किसकी होगी, यह अपरिभाषित है।विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने की बात एक बड़ा कदम है, लेकिन यहां भी 'भारतीय ट्रस्ट कानून' आड़े आता है।

एसडीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण

35 बीघा जमीन पर उगाई जाएगी नेपियर घास

अब साल भर गौशालाओं में उपलब्ध होगा चारा,फरवरी में होगी घास की बुवाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। गोवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश व मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी बिल्हौर डॉ संजीव दीक्षित ने गुरुवार को विकासखंड शिवराजपुर स्थित वृहद गोआश्रय स्थल कमालपुर खोंदन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और उन्हें और बेहतर करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मौजूद रहे। एसडीएम ने गोपालकों को गोशाला में साफ-सफाई बनाए रखने और गोवंश की समुचित देखरेख करने के निर्देश दिए। गोवंश के लिए हरे चारे की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगभग 35 बीघा सरकारी भूमि को राजस्व निरीक्षक,

- औचक निरीक्षण में पाई गई कमियों में तुरंत सुधार का निर्देश
- गोपालकों को स्वच्छता और पशु देखभाल के सख्त निर्देश

सखरेज और चकबंदी विभाग की टीम द्वारा सीमांकन कर चिन्हित किया गया है। उक्त भूमि पर पिलर व बाड़ लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। फरवरी माह में यहां नैपियर घास की बुवाई कर गौशाला के साथ आसपास की अन्य गौशालाओं में भी हरे चारे की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

एसडीएम ने निरीक्षण में पाई गई कमियों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए खंड विकास अधिकारी शिवराजपुर को एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने को कहा। प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र की गौशालाओं की व्यवस्था और सुदृढ़ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मिट्टी खनन रोक के बावजूद जारी, चकबंदी प्रभावित

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर(कानपुर) चौबेपुर क्षेत्र के पांच गांवों में चकबंदी के दौरान भी मिट्टी खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। खासकर मरखरा गांव में लगातार हो रहे खनन ने कच्चे रास्तों और खेतों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, खेतों से आठ फीट तक मिट्टी खनन किया जा चुका है। इससे न सिर्फ जमीन का मूल्यांकन मुश्किल हो गया है, बल्कि चकबंदी प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।

ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि खनन करने वाले लोग ईंट भट्टों के नाम पर अनुमति लेकर मिट्टी उठाते रहे हैं। चकबंदी अधिकारी का कहना है कि सूचना मिलने पर एसीओ और लेखपाल से जांच कर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया, और खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई।

- शिवराजपुर के गंगा तटवर्ती गांवों में भी बिना अनुमति खनन

आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खनन?

प्रतिबंध के बावजूद मरखरा और आसपास के गांवों में खनन जारी होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायतों और अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई न होना किसी ऊपर तक संरक्षण की ओर इशारा करता है। स्थानीय चर्चा में यह भी है कि प्रभावशाली संरक्षण के चलते ही खनन माफिया बेखौफ हैं।

सूत्रों के अनुसार, मंधना से बिल्हौर तक अवैध मिट्टी खनन का कारोबार तेजी से चल रहा है और शिवराजपुर के गंगा तटवर्ती गांवों में भी बिना अनुमति खनन हो रहा है।

मिट्टी खनन के कारण धंसा और उखड़ा चकमार्ग।

जगह-जगह सपा की पीडीए चौपाल लगी, ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं

बिजली, पेंशन और सुरक्षा मुद्दों पर समाधान का भरोसा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)।ककवन विकास खण्ड के उत्तमपुर गाँव में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली विभाग की गड़बड़ियों, पेंशन भुगतान में देरी और रात्रिकालीन सुरक्षा की समस्याएँ उठाईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि सपा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह रहीं।

ग्रामीणों ने बढ़े हुए बिजली बिल, नए कनेक्शन में देरी और कथित अवैध वसूली की शिकायत की। वहीं पेंशन योजनाओं में एक वर्ष से लंबित आवेदनों को लेकर नाराजगी जताई गई। विनय यादव ने कहा कि पेंशन आवेदनों से जुड़े खर्च वह स्वयं वहन करेंगे और समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुँचाया जाएगा।

रचना सिंह ने कहा कि पीडीए समाज के हर मुद्दे पर वह जनता के साथ खड़ी रहेंगी।

बिजली, पेंशन और सुरक्षा मुद्दों पर समाधान का भरोसा

बिल्हौर(कानपुर)।ककवन विकास खण्ड के उत्तमपुर गाँव में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली विभाग की गड़बड़ियों, पेंशन भुगतान में देरी और रात्रिकालीन सुरक्षा की समस्याएँ उठाईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि सपा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह रहीं। ग्रामीणों ने बढ़े हुए बिजली बिल, नए कनेक्शन में देरी और कथित अवैध वसूली की शिकायत की। वहीं पेंशन योजनाओं में एक वर्ष से लंबित आवेदनों को लेकर नाराजगी जताई गई। विनय यादव ने कहा कि पेंशन आवेदनों से जुड़े खर्च वह स्वयं वहन करेंगे और समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुँचाया जाएगा । चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तमपुर में सपा की पीडीए चौपाल, ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं।

बिल्हौर में भूमि स्वामित्व पर घमासान निस्तारण की प्रक्रिया पर उठे सवाल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील क्षेत्र में भूमि स्वामित्व को लेकर उपजा विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्ष अपने-अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन महीनों बीतने के बावजूद निस्तारण न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। मामला तहसील समाधान दिवस से लेकर आईजीआरएस पोर्टल तक पहुंच चुका है, जहां बार-बार प्रार्थनापत्र देकर हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

जानकारी के अनुसार उपजिलाधिकारी कार्यालय और थाना बिल्हौर के ठीक समीप स्थित एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा

- मामला तहसील समाधान दिवस से लेकर आईजीआरएस पोर्टल तक पहुंच चुका

है। बताया जाता है कि उक्त भूमि गजेंद्र सिंह द्वारा सुचेता पत्नी मनोज राजपूत (एडवोकेट) से विधिवत क्रय की गई थी। भूलेख अभिलेखों में यह भूमि नीति पत्नी अनूप के नाम दर्ज है और धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत अकृषक घोषित है। इसके बावजूद अकबरपुर, कानपुर देहात निवासी शिवप्रसाद पुत्र गोपाल द्वारा उक्त भूमि पर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोप है कि वैधानिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर जबरन कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

सूत्रों की मानें तो संबंधित व्यक्ति द्वारा पूर्व में तहसील अधिकारियों और स्थानीय लेखपाल के खिलाफ शिकायतें की गई थीं। प्रशासनिक स्तर पर कराई गई जांच में इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, इसके बावजूद विवाद को जानबूझकर उलझाए रखने की चर्चा आम है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सभी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद भी कार्रवाई में हो रही देरी समझ से परे है। तहसील समाधान दिवस और आईजीआरएस के माध्यम से निष्पक्ष जांच और शीघ्र निस्तारण की मांग की गई है।

आयुष्मान कार्ड धारक मरीज को बंधक बनाकर की अभद्रता

» पहले भी कई मरीजों से अभद्रता और लापरवाही कर चुका है अस्पताल संचालक

अकबरपुर में निजी अस्पताल नोवा ग्रेस हॉस्टिपल की मनमानी उजागर

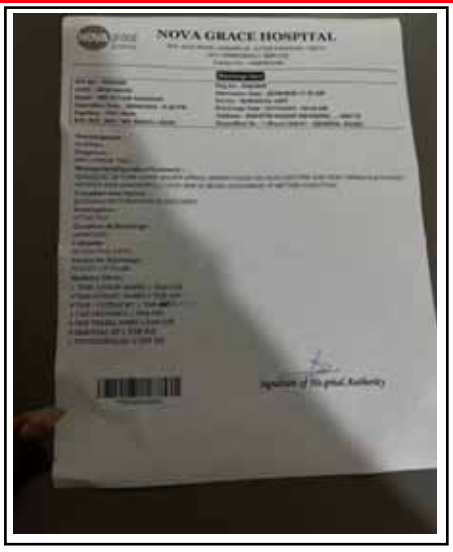

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले में निजी अस्पतालों की मनमानी और गरीब मरीजों के शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। अकबरपुर माती रोड स्थित नोवा ग्रेस अस्पताल पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भर्ती एक बुजुर्ग मरीज को बंधक बनाकर रखने, इलाज में लापरवाही और अवैध धन वसूली के आरोप लगे हैं। रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे एक सामाजिक कार्यकर्ता को सिकंदरा निवासी एक युवक का फोन आया। युवक ने बताया कि उसके पिता को नोवा ग्रेस अस्पताल में जबरन रोका गया है और पैसे न देने पर छुट्टी नहीं दी जा रही। मामला गंभीर देख सामाजिक कार्यकर्ता तत्काल अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की।

पीड़ित युवक ने बताया कि लगभग दो माह पूर्व उसके पिता का प्रोस्टेट का ऑपरेशन इसी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया गया था, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। दोबारा तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ने फिर से आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करने का आश्वासन देकर भर्ती कर लिया। इसके बाद दो दिनों तक मरीज को अस्पताल में रखा गया, लेकिन न तो कोई इलाज किया गया और न ही मरीज की स्थिति की स्पष्ट जानकारी दी गई।

आरोप है कि बार-बार मांगने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने पहले किए गए ऑपरेशन की फाइल और रिपोर्ट भी नहीं दी। जब परिजनों ने मरीज को किसी अन्य अस्पताल ले जाने की इच्छा जताई तो अस्पताल प्रबंधन ने तेरह हजार रुपये जमा करने की शर्त रख दी। परिजनों का कहना है कि पैसे न होने के कारण मरीज को बंधक बनाकर रखा गया और आयुष्मान योजना से धन प्राप्त करने के लिए जबरन दोबारा ऑपरेशन कराने का दबाव बनाया जा रहा था।

सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने पर अस्पताल मालिक ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डायल एक सौ बारह के माध्यम से पुलिस मौके पर पहुंची और मरीज को सकुशल मुक्त कराया गया।

पुलिस की मौजूदगी में दो माह पूर्व किए गए ऑपरेशन से संबंधित फाइल और रिपोर्ट भी परिजनों को सौंपी गई। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि मानकविहीन तरीके से संचालित यह अस्पताल गरीब मरीजों को निशाना बनाकर आयुष्मान योजना के नाम पर लूट कर रहा है।

एसपी ने ली सलामी, गारद का भी जायजा

पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में गारद रजिस्टरों को देखा, दिए कई निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने गारद का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश भी दिए।

परेड के बाद टोलीवार ड्रिल कराई गई।

एसपी ने ट्रेनिंग ले रहे रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन, समयबद्धता, शिक्षण पद्धति, फिजिकल ट्रेनिंग एवं व्यवहारिक ज्ञान पर भी ध्यान दिया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक श्रध्दा नरेंद्र पाण्डेय ने पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में पहुंचकर सभी गारद रजिस्टरों को देखा। गारद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गारद कमांडरों को निर्देश दिए।

संदिग्ध हालात में रेल कर्मी ने दी जान तीन अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप

तार चोरी के आरोप से परेशान होकर जान देने का दावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात माती। गजनेर थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव निवासी रेलवे कर्मी ने गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में सरवनखेड़ाझुरनिया मार्ग किनारे खड़े आम के पेड़ से मफलर के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में मृतक ने रेलवे विभाग के तीन कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कहते हुए प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का दावा किया है। मृतक की पहचान हृदयपुर गांव निवासी विजय पाल (45) के रूप में हुई है, जो रेलवे विभाग में सहायक इलेक्ट्रिशियन के पद पर पुखरायां में तैनात थे।

मृतक की फाइल फोटो

घटना स्थल पर रोते-बिलखते महिला

जानकारी के मुताबिक वह प्रतिदिन घर से सवारी द्वारा रनिया और वहां से पुखरायां ड्यूटी पर जाते थे।

गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे वह ड्यूटी जाने की बात कहकर हाथ में टिफिन लेकर पैदल घर से निकले थे। कुछ देर बाद रनिया सरवनखेड़ा मार्ग पर हृदयपुर व सैयदूदा गांव के बीच संजीव गुप्ता के आम के पेड़ से उनका शव मफलर के सहारे लटका मिला।

आत्महत्या से पहले विजय पाल ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के दो सीनियर कर्मियों अवध किशोर और अखिलेश पांडे तथा एक सहयोगी रोहित पर 15 क्विंटल तार चोरी का आरोप लगाकर लगातार मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। वीडियो में मृतक ने स्वीकार किया है कि उसके पास 67 किलो तार था, क्योंकि उस दिन उसे ड्यूटी से अनुपस्थित दिखा दिया गया था। उसने वीडियो में कहा कि तीनों लोग उसकी जान के भूखे हैं और लगातार दबाव बनाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कहते हुए उसने यह वीडियो अपने बेटे अरुण को भेज दिया। स्वराज इंडिया वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है।

सुबह करीब नौ बजे बेटे ने वीडियो देखा और पिता की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान सड़क किनारे पेड़ से शव लटका मिला। ग्रामीणों ने शव को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मृतक के बेटे अरुण ने यूपी 112 पर सूचना दी। सूचना पर गजनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो और परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच करती गजनेर पुलिस

अवैध तमंचा कारतूस समेत शातिर हुआ गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। भोगनीपुर पुलिस ने चोरी की नीयत से घूम रहे एक शातिर को तमंचा व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि एक युवक को जरैलापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशीतमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बबलू, निवासी ग्राम ततारपुर, थाना सट्टी बताया। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

ठंड से कांप रहे लोगों का अलाव बना सहारा, ली राहत की सांस

» कोहरे से गेहूं की फसल को हो रहा लाभ, लाही,आलू, चना की फसल को नुकसान

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। जनवरी का पहला हफ्ता व्यतीत होने के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है कड़ाके की ठंड में लोग घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में अलाव ही लोगों का सहारा बन रहा है।

रसूलाबाद क्षेत्र में इन दिनों नव वर्ष के पहले हफ्ते में भी खूब ठंड पड़ रही है सुबह से कोहरा और गलन होने से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं दो पहिया वाहन चलाने में तो और भी मुश्किल आ रही है।

गुरुवार को मौसम बहुत सर्द रहा रात से गिरना शुरू हुआ कोहरा पूरे दिन छाया रहा वहीं गलन बढ़ने से पूरे दिन लोग अलाव के पास बैठकर शरीर सेकते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा

मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है सड़क पर निकलने वाले दोपहिया वाहन चालकों ने बताया की ठंड में उनके हाथ काम नहीं कर रहे ऐसे में वह भी अलाव के पास रुक कर हाथ सकते हुए नजर आए। वहीं कोहरे से गेहूं की फसल को तो लाभ हो रहा है लेकिन लाही,आलू, चना की फसल को काफी नुकसान हो रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 । **Email:** swarajindia2023@gmail.com । **Mob:** 7800009853, । **Website:** www.swarajindianews.com । **(समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)** प्रादेशिक कार्यालय:4ए/5,119/10बी, खान बिल्डिंग, पार्क रोड हजरतगंज

शिकायत निस्तारण में कानपुर देहात पुलिस बनी प्रदेश में नंबर वन

शंकर सिंह/स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण के क्षेत्र में कानपुर देहात पुलिस ने प्रदेश स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक तथा कानपुर जोन एडीजी आलोक सिंह के निर्देशन और कानपुर रेंज आईजी हरीश चन्दर के मार्गदर्शन में, एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के प्रभावी नेतृत्व में कानपुर देहात पुलिस ने आईजीआरएस दिसंबर 2025 की रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस के

आईजीआरएस रैंकिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि, एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में जनपद को पहला स्थान

मूल्यांकन में कानपुर देहात जनपद ने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। थानावार रैंकिंग में थाना अकबरपुर, मंगलपुर, रसूलाबाद, शिवली, रूरा, गजनेर, महिला थाना, भोगनीपुर, देवराहाट, सट्टी, डेरापुर, बरौर और अमराहट द्वारा शिकायतों का सौ प्रतिशत निस्तारण किया गया। जनपद के कुल सत्रह थानों में से तेरह थानों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा।एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, ईमानदार और समयबद्ध विधिक निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर हुई समीक्षा में कानपुर देहात जनपद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया।

त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण बनी पहचान

शिकायत निस्तारण की इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि को एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय की कर्तव्यनिष्ठा, न्यायप्रिय कार्यशैली और कुशल नेतृत्व का परिणाम माना जा रहा है। उनके कार्यभार संभालने के बाद से जनपद में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए गए हैं। इस उपलब्धि पर एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी तथा उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रदेश स्तर पर इस रैंकिंग को बनाए रखने के लिए निरंतर इसी लगन और प्रतिबद्धता से कार्य करते रहने का संदेश दिया और सभी को शाबाशी दी।

रूरा क्षेत्र से विवाहिता लापता पुलिस कर रही तलाश

» परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र से एक 25 वर्षीय विवाहित महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के अंदाया गांव निवासी लाल जी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 25 वर्षीय पुत्रवधू शिवानी राठौर मंगलवार रात करीब 10 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गई। देर रात तक वापस न लौटने पर शिवानी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन बंद मिला। थाना प्रभारी अमित शुक्ला ने कहा कि लापता महिला की तलाश के लिए पुलिस टीम संभावित स्थानों पर जांच कर रही है।

डीएम की सख्ती के बाद अवैध खनन में लगी जेसीबी पकड़ी

» खेतों में हो रहा था मिट्टी खनन, तहसील के अफसरों ने शुरू किया एक्शन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। डीएम कपिल सिंह की सख्ती के बाद तहसील प्रशासन ने अवैध खनन पर एक्शन शुरू किया है। गुरुवार अवैध रूप से मिट्टी खनन में लगी एक जेसीबी गाड़ी को पकड़ा।

तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा कहिंजरी के ग्राम पंचायत मकरंदपुर कहिंजरी में अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी खनन पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से मिट्टी खनन की सूचना उपजिलाधिकारी रसूलाबाद को मिली। मौके पर राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार लेखपाल अंकित कुशवाहा मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से जेसीबी मशीन को पकड़ा। हालांकि खनन कर्ता मौके से फरार हो गए केवल जेसीबी चालक मिला। उपजिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि मकरंदपुर कहिंजरी गांव में जेसीबी मशीन से मिट्टी के अवैध खनन की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल राजस्व टीम को मौके पर भेजा। राजस्व टीम में कानून गो अनिल कुमार, लेखपाल अंकित कुशवाहा, लेखपाल उत्तम और लेखपाल प्रियंका दुबे मौके पर पहुंची। जहां पर उन्होंने गाटा संख्या 1160 पर राम देवी, प्रेमवती और रामगोपाल आदि के खेतों में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। राजस्व टीम ने चालक और जेसीबी को कब्जे में लेते हुए और रसूलाबाद कोतवाली भेजा। जेसीबी चालक ने बताया कि मशीन मैथा तहसील के गहरा गांव निवासी सरोज कुमार वर्मा की है। इस पर प्रशासन एसडीएम सर्वेश सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

रायबरेली में नृशंस हत्या

सिर काटकर ले गए हत्यारे

» भांजी के घर आए युवक का शव नाले में फेंका, 150 मीटर तक घसीटने के निशान

» आधार कार्ड से हुई पहचान, एसपी ने बनाई जांच टीमें

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

रायबरेली । रायबरेली जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जायस थाना क्षेत्र के मुखेतिया गांव के पास बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ दूरी पर नईया नाले में एक युवक का सिर कटा शव मिलने से इलाके में

सनसनी फैल गई। हत्यारों ने गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को करीब डेढ़ सौ मीटर तक घसीटा और सिर अपने साथ ले गए। गुरुवार तड़के शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान प्रतापगढ़ जिले के धर्मशाला चौक निवासी 50 वर्षीय विजय पुत्र बेनी माधव के रूप में हुई। पहचान होते ही मृतक की भांजी अलका भी मौके पर पहुंची और शिनाख्त की। उसने बताया कि विजय बुधवार दोपहर उनके घर आए थे और रात करीब साढ़े दस बजे एक फोन आने के बाद देवा शरीफ जाने की बात कहकर निकले थे, इसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ ।पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक ने मौके का मुआयना किया और खुलासे के लिए कई टीमें गठित कीं। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर हत्या की गई, वहां से नाले तक खून के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को घसीटकर फेंका गया। मृतक का मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हुआ है ।अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के कटे सिर की तलाश जारी है। बताया गया कि विजय झाड़-फूंक का काम करता था और देवा शरीफ का भक्त था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा में अंकिता शर्मा सफल बेसिक विभाग में खुशी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। राज कुमार शर्मा की सुपुत्री अंकिता शर्मा ने ऑल इंडिया बार काउंसिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल अपने परिवार बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग को भी गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। अंकिता शर्मा वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तिरुवलूर से एलएलएम फाइनल ईयर की छात्रा हैं। उनका लक्ष्य न्यायाधीश बनकर समाज को न्याय दिलाना है, जिसे वे शीघ्र ही साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं।

इस मौके पर यूटा संगठन के वरिष्ठ शिक्षक नेता बलबीर सिंह ने अंकिता को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से अंकिता बिटिया को ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं। अंकिता की इस सफलता पर उनके माता-पिता सहित परिवार के सभी सदस्यों को भी लोगों ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

फर्जी शिकायत पर रोक दिया दिव्यांग लिपिक का वेतन

पत्नी ने एडी-सीएमओ से लगाई वेतन दिलाने की गुहार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।स्वास्थ्य विभाग के भीतर कथित अफसरशाही और महिला कर्मचारियों की फर्जी शिकायत का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तारुन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर कार्यरत दिव्यांग लिपिक शशि भूषण तिवारी को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप उनकी पत्नी प्रीती तिवारी ने लगाया है। पीड़िता ने अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अयोध्या मंडल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से न्याय की गुहार लगाई है।

प्रीती तिवारी का आरोप है कि उनके दिव्यांग पति को सीएचसी मिल्कीपुर की महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक देविका शुक्ला, रमा सिंह और एएनएम गीता देवी द्वारा साजिशन फंसाया गया है। आरोप लगाया गया कि शशि भूषण तिवारी ने तीनों कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक गायब कर दी, जबकि उस समय वे मिल्कीपुर सीएचसी में तैनात थे। इन कथित आरोपों

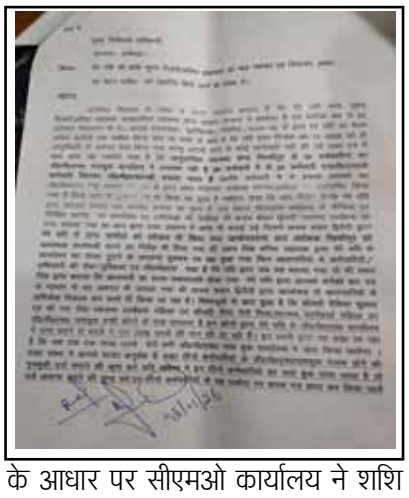

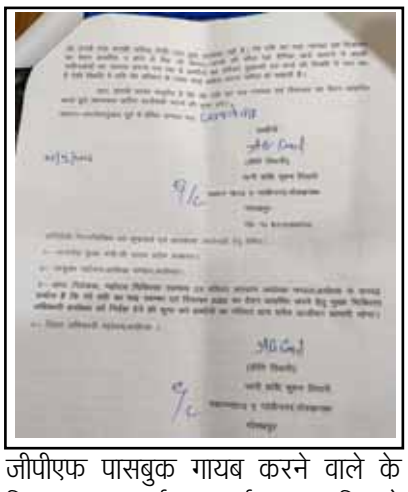

के आधार पर सीएमओ कार्यालय ने शशि भूषण तिवारी का नवंबर और दिसंबर माह का वेतन रोक दिया। प्रीती तिवारी का कहना है कि बिना जांच, बिना दोष सिद्ध हुए उनके पति को दंडित कर दिया गया, जो सीधे-सीधे अन्याय है। उन्होंने बताया कि वेतन रुकने से पूरा परिवार आर्थिक तंगी में आ गया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और घर चलाना मुश्किल हो गया है।

प्रीती तिवारी ने अपने प्रार्थना पत्र में साफ लिखा है कि जिन तीन महिला कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक गायब होने का आरोप लगाया गया है, वह पासबुक उन्हीं के पास है। इसके बावजूद झूठी शिकायत कर उनके पति को फंसाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि यदि सीएमओ निष्पक्ष हैं तो जीपीएफ पासबुक गायब करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि उनके पति का रोका गया वेतन तत्काल जारी नहीं किया गया और उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी, तो वह परिवार सहित मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने को मजबूर होंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की होगी। इस पूरे मामले में सीएमओ डॉ0 सुशील बनियान ने कहा यदि शिकायत करने वाली कर्मचारी लिखित में दे दें कि उनकी जीपीएफ पासबुक मिल गई है, तो शशि भूषण तिवारी का वेतन भुगतान करवा दिया जाएगा। सीएचसी प्रभारी मिल्कीपुर ने भी लगभग यही बात दोहराई।

अभी निर्मला हॉस्पिटल को कोई क्लीन चिट नहीं!

» 15 दिसंबर का इंजेक्शन- क्या एक साथ दी गई पांच डोज ने ली सरोज की जान?

» निर्मला हॉस्पिटल मौत कांड में नर्सें केंद्र में, पुलिस के सामने आईं 'अंडरग्राउंड' नर्सें

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।निर्मला हॉस्पिटल में हुई सरोज कौशल की रहस्यमय मौत अब केवल एक मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह निजी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं के डोज और निगरानी तंत्र पर बड़ा सवाल बन चुकी है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कहानी का केंद्र 15 दिसंबर और उस दिन दिए गए हेपरिन इंजेक्शन पर सिमटता जा रहा है।

सीएमओ डॉ. सुशील कुमार बानियान ने बताया कि ओवरडोज से मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। यह देखना है कि इंजेक्शन किसके निर्देश पर दिया गया और इलाज में और क्या लापरवाही हुई। नर्सों के बयान बेहद अहम हैं।

सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी का कहना है कि दोनों नर्सें गुरुवार को सीएमओ कार्यालय पहुंची थीं। शुक्रवार को पुलिस के समक्ष उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि हेपरिन डोज का पूरा गणित यह है कि एक वायल में 5 डोज होते है।11 दिसंबर को उसे पहली डोज दी गई। 12 दिसंबर को उसी वायल की 3 डोज और दी गयी।13 दिसंबर को 5वीं डोज और वायल समाप्त हो गया। दूसरी वायल से 13 दिसंबर को 2 डोज 14 दिसंबर को 3 डोज और 15 दिसंबर को आरोप है कि पूरी वायल (5 डोज) एक साथ दे दी गयी। यही वह बिंदु है, जहां से सरोज की मौत की कहानी खून में लिखी जाती दिख रही है। निर्मला हॉस्पिटल प्रकरण अब केवल एक मरीज की मौत नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली, स्टाफ की योग्यता और सरकारी निगरानी पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। दो नर्सों के बयान तय करेंगे कि यह चिकित्सकीय चूक थी, आपराधिक लापरवाही या सिस्टम की सोची-समझी चूक।

सूत्रों के मुताबिक, सरोज को 11 दिसंबर से हेपरिन इंजेक्शन दिया जा रहा था। 14 दिसंबर तक यह इंजेक्शन पूरी तरह नियमानुसार पांच-पांच डोज में दिया गया। लेकिन 15 दिसंबर को वही पांच डोज एक साथ दिए जाने की प्रबल आशंका अब जांच का सबसे अहम बिंदु बन चुकी है। जांच की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि सरोज का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। यदि चीरफाड़ होती तो ब्लीडिंग के स्पष्ट संकेत मिलते और यह तय हो जाता कि मौत ओवरडोज से हुई या किसी अन्य कारण से। अब स्वास्थ्य विभाग मेडिकल रिकॉर्ड, दवाओं की खपत, नर्सों के बयान और डॉक्टरों की लिखित राय के सहारे सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।

15 दिसंबर को ड्यूटी पर तैनात रहीं दो स्टाफ नर्सें अचानक निर्मला हॉस्पिटल से गायब हो गईं। सूत्रों का दावा है कि पुलिस की कॉल और स्वास्थ्य विभाग के दबाव के बाद ही दोनों नर्सें सीएमओ कार्यालय पहुंचीं। इन्हीं दो नर्सों के बयान पर अब पूरी जांच टिकी हुई है। जांच अधिकारी मानते हैं कि क्रॉस क्वेश्चनिंग के बिना न तो क्लोजर रिपोर्ट बनेगी और न ही किसी को क्लीन चिट मिल सकेगी।

निर्मला हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने 10 दिसंबर को सरोज का परीक्षण किया था, ने अपने बयान में साफ लिखा है हेपरिन यदि पांच गुना ज्यादा मात्रा में दी जाए तो ब्लीडिंग होना तय है और ऐसी स्थिति में मौत स्वाभाविक है।

हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसकी पुख्ता पुष्टि पोस्टमार्टम से ही हो सकती थी, जो नहीं हो सका। अब जांच का रुख बदल चुका है। सवाल यह नहीं है कि मौत कैसे हुई, बल्कि यह है कि इंजेक्शन किसके कहने पर दिया गया? क्या डॉक्टर ने एक साथ डोज देने का निर्देश दिया था? या फिर नर्सों की लापरवाही या जल्दबाजी ने मरीज की जान ले ली? स्वास्थ्य विभाग यह भी जांच रहा है कि क्या उस समय मरीज में कोई ऐसी जटिलता उभर रही थी, जिसे नजरअंदाज किया गया।

30 साल का गन्ना भुगतान, 90 साल का दर्द, आत्मदाह की चेतावनी

गन्ना भुगतान न मिलने से परेशान 90 वर्षीय किसान ने तहसील में सुनाई व्यथा , डीएम को शिकायत भेजी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जनपद अयोध्या के बीकापुर तहसील क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। 90 वर्षीय गन्ना किसान राम तेज वर्मा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर गन्ना भुगतान न होने की समस्या का समाधान न होने पर तहसील परिसर में आत्मदाह की चेतावनी दी है।

किसान राम तेज वर्मा के अनुसार, उनके पिता स्वर्गीय त्रिवेणी वर्मा ने वर्ष 1990-91 में केएम शुगर मिल मसौधा को चार ट्राली गन्ना आपूर्ति किया था, लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार प्रयास किए गए, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है।

राम तेज वर्मा का आरोप है कि उन्होंने बीकापुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी और उन्हें वापस भेज दिया गया। इससे आहत होकर उन्होंने अब जिलाधिकारी को ऑनलाइन रजिस्ट्री के

माध्यम से सूचित किया है कि यदि आगामी तहसील दिवस तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वह तहसील परिसर में आत्मदाह करने या कोई अन्य कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

पीड़ित किसान ने यह भी आरोप लगाया कि शुगर मिल अधिकारियों द्वारा उन्हें यह कहकर गुमराह किया गया कि वे दीवानी मुकदमा हार चुके हैं, जबकि उन्होंने कभी कोई मुकदमा दायर ही नहीं किया।

किसान का कहना है कि गन्ना भुगतान से जुड़े सभी साक्ष्य उन्होंने जिलाधिकारी को भेज दिए हैं। मामले ने एक बार फिर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शुरू हुआ अशोक लेलैंड का ईवी प्लांट, उत्तर प्रदेश को मिली पहली इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया उद्घाटन

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सरोजनी नगर में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस अत्याधुनिक संयंत्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से किया।

उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और वहां तैयार की जा रही इलेक्ट्रिक बसों को अंदर से देखा। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। नेताओं ने प्लांट को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बताया।

यह फैक्ट्री सरोजनी नगर क्षेत्र में करीब 70 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित की गई है। कंपनी और सरकार के अनुसार इसका निर्माण महज 16 महीनों में पूरा किया गया, जिसे रिकॉर्ड समय माना जा रहा है। प्लांट को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया गया है और इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, ताकि उत्पादन क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सके।

फिलहाल इस संयंत्र में इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रैवलर और इलेक्ट्रिक लोडिंग वाहन तैयार किए जाएंगे। यह उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस निर्माण फैक्ट्री है। कंपनी के मुताबिक शुरुआती चरण में यहां हर साल करीब 2,500 इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण किया जाएगा, जिसे आने वाले समय में बढ़ाकर 5,000 बस प्रति वर्ष तक किया जाएगा।

इस परियोजना से न सिर्फ स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि यह प्लांट उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मथुरा, गाजियाबाद में बारिश से सर्दी और बढ़ी सोनभद्र सबसे ठंडा रहा

- कोहरे से वाराणसी पहुंचा इंडिगो का विमान करीब 70 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाता रहा. 10 और फ्लाइट्स को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। बर्फीली हवाओं के बीच बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह-सुबह मथुरा में तेज बारिश हुई। गाजियाबाद में भी बूंदाबांदी से ठंड में इजाफा हुआ है। अयोध्या, झांसी, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, मेरठ समेत करीब 35 जनपद भी घने कोहरे की चपेट में है। कई जगह तो दृश्यता शून्य पहुंच गई है। सड़क पर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है।

जनवरी में काशी में 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां अधिकतम तापमान 11.4एष्ट रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 17 जनवरी 2003 में अधिकतम तापमान 11.6एष्ट दर्ज किया गया था। वहीं लखनऊ समेत 33 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में सोनभद्र सबसे ठंडा रहा. पारा 4एष्ट रिकॉर्ड किया गया. गोरखपुर-काशी में पारा 4.8एष्ट, बरेली-सुल्तानपुर में 5एष्ट रहा। लखनऊ-कौशांबी-मेरठ में 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर में 12वीं तक स्कूल 14 जनवरी, मथुरा, प्रयागराज, बरेली-अंबेडकरनगर, कन्नौज, चंदौली में 10 जनवरी तक बंद है।

कोहरे से सड़क, रेल और हवाई सफर प्रभावित

कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई सफर बुरी तरह प्रभावित हुआ. गोरखपुर, झांसी समेत तमाम रेलवे स्टेशन पर 70 ट्रेनें लेट हैं. बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल (02563) ट्रेन 27 घंटे लेट रही. वाराणसी एयरपोर्ट पर ब्लैक आउट जैसा मंजर रहा. वाराणसी पहुंचा इंडिगो का विमान करीब 70 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाता रहा. 10 और फ्लाइट्स को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। 12 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी.

पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदलेगा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों से यूपी में ठंडी पछुआ हवा आ रही है। जनवरी के पहले हफ्ते प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ी. धूप बेअसर रही जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रही। फिलहाल उत्तरी पंजाब में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में धीरे-धीरे बदलेगा। तीन दिन मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा। 11 जनवरी से कोहरे में कमी आ सकती है। जिससे सर्दी भी कुछ कम होगी।

गन्ना किसानों की जेब पर डाका नहीं, अफसरों पर चलेगा डंडा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गन्ना किसानों से अवैध वसूली के मामलों पर गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चीनी मिल गेट और वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग-अनलोडिंग के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क लिया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली-1954 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि क्रय केंद्रों पर गन्ना तौल के दौरान घटतौली की जा रही है और लोडिंग-अनलोडिंग के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। इस पर उप चीनी आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त और गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी किसी भी शिकायत की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चीनी मिलों और क्रय केंद्रों पर ताजा, स्वच्छ और साफ-सुथरे गन्ने की आपूर्ति ही स्वीकार की जाए।

इसी कड़ी में सरकार ने बिजली व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने मिर्जापुर और सीतापुर के दो मुख्य अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दोनों पर अपेक्षित राजस्व वसूली न होने, ट्रांसफार्मरों के अधिक क्षतिग्रस्त होने और बिजली आपूर्ति से जुड़े कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप थे। यह कार्रवाई गुरुवार को प्रदेश की सभी डिस्कॉम की समीक्षा बैठक के दौरान की गई, जिससे साफ है कि सरकार किसानों और उपभोक्ताओं के हितों से समझौता करने के मूड में नहीं है।

- सीएम योगी की गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क वसूली पर सख्त चेतावनी
- बिजली व्यवस्था में लापरवाही करने पर दो चीफ इंजीनियर तत्काल हटाए गए